भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2867

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं की समीक्षा

2867. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत, अनुमोदित और पूर्ण की गई सड़क परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई देरी के कारणों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और भविष्य में ऐसी देरी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय और कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत विशेषकर बिहार में कितनी प्रगति हुई है और स्वीकृत, पूर्ण और लंबित सड़कों की लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस कार्य में किसी भी देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और निर्मित सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा **pmgsy.dord.gov.in -> Progress Monitoring -> Financial Yearwise Achievement** पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किए गए व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **pmgsy.dord.gov.in -> Financial Progress -> Fund Position Report Live** पर देखा जा सकता है।

(ख) से (ग) मंत्रालय समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करता है और उन कारकों की पहचान की है जो कभी-कभी कार्यान्वयन की गति को बाधित करते हैं। इनमें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण सीमित कार्य मौसम, वन मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाई, कच्चे माल की कमी और कानूनी या भूमि संबंधी बाधाओं जैसी चुनौतियां शामिल हैं। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में, ये चुनौतियां अक्सर कठिन भू-भाग और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण और बढ़ जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और कार्यान्वयन एजेंसियों की सीमित तकनीकी या संविदात्मक क्षमता भी कार्यों के समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

मंत्रालय ने इन बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, एक मजबूत बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित किया है। क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से प्रगति की कड़ाई से जांच की जाती है। मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा अंतर-विभागीय मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की जाती है। जमीनी स्तर पर, माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) निरीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत, निर्मित और लंबित सड़क परियोजनाओं का विवरण (बिहार राज्य सहित) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार **pmgsy.dord.gov.in -> Proposals -> Statewise List of Roads** पर देखा जा सकता है।

***